उन्हें नियमित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

मध्य प्रदेश में डाकघरों को मुख्य डाकघर का दर्जा दिया जाना

248. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में किसी डाकघर को मुख्य डाकघर का दर्जा दिया जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्य राज्यों में स्थित ऐसे डाकघरों की संख्या की तुलना में मध्य प्रदेश में मुख्य डाकघरों की संख्या कितनी है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) मौजूदा विभागीय मानदंडों के अनुसार मध्य प्रदेश में किसी भी उप डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं बनता है।

(ग) मध्य प्रदेश में 52 प्रधान डाकघर हैं। अन्य राज्यों में प्रधान डाकघरों की सं० निम्नानुसार है :

1.	आंध्र प्रदेश	104
2.	असम	16
3.	बिहार	42
4.	दिल्ली	9
5.	गुजरात	42
6.	हरियाणा	15
7.	हिमाचल प्रदेश	17
8.	जम्मू और कश्मीर	9
9.	कर्नाटक	69
10.	केरल	51
11.	महाराष्ट्र (गोवा राज्य सहित)	63
12.	पूर्वोत्तर राज्य	9
13.	उड़ीसा	35
14.	पंजाब	22
15.	राजस्थान	55
16.	तमिलनाडु	93
17.	उत्तर प्रदेश	85
18.	पश्चिम बंगाल (अंडमान निकोबार द्वीप और सिक्किम राज्य सहित)	46

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए बजट प्रावधान

249. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बजट में कितना प्रावधान रखा गया है और उनमें से अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश में इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ ऐसे उपमार्ग भी हैं जो निर्माणाधीन हैं और उनके लिए बजट में क्या प्रावधान रखा गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 1991-92 के लिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए अनन्तिम तौर पर 1082.32 लाख रु० का प्रावधान किया गया है। अब तक 265 लाख रु० की राशि जारी की जा चुकी है और मई, 1991 तक 262.56 लाख रु० खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर नर्मदा पर एक ऊंचे पुल सहित 5.4 कि. मी. लम्बे जबलपुर "बाईपास" का एक हिस्सा निर्माणाधीन है। 1991–92 के दौरान इस कार्य के लिए बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि 33.35 लाख रु. है।

Conversion of State Highways into National Highways in Tamil Nadu

250. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any request from the Tamil Nadu Government to convert:

(i) Madurai-Tenkasi State Highways;

(ii) Trinulveli-Kollam State Highway into the National Highways-and

(b) if so, what is the action taken by Government in the matter?

THE MINISTER' OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir.

(b) A decision in this regard can be taken only after finalisation of the 8th Five Year Plan, having regard to different factors, such as the criteria prescribed for new National Highways, recommendations made by the National Transport Policy Committee, *inter-se* priority of various proposals, availability of funds etc.

Indo-China Relations

251. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN:

MISS SAROJ KHAPARDE:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what steps are being taken by Government to maintain cordial relationship with China and what is the response of the Chinese Government;

(b) what steps are being taken to settle the border dispute between India and China;

(c) whether there is any Rending invitation from the Chinese Government to either the Prime Minister or the Foreign Minister to visit China and whether there is any pending invitation from India to the Chinese Head of State or Foreign Minister to visit India;

(d) what are the ultimate results of the meetings of official spokesman of two countries which were held in the recent past to discuss the border dispute and other allied topics;

(e) whether Government is aware of the provocative innuendos about alleged Indian expansionism and hegemonism presented in a paper, at a Seminar in Colombo recently by an Associate Professor of Beijing University; and

(f) whether any clarification was sought on this paper from the authorities in Beijijng or from the Ambas, sador of China in Delhi to ascertain whether it is the thinking of the individual or thinking of the Chinese Government?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) Since the visit of the then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi to China in 1988, there has been, a marked improvement in India-China relations. The high level political dialogue with China on matters of mutual concern has gathered momentum. The scale of scientific, technical and cultural exchanges has been steadily expanded. Agreement has been reached in principle on reopening Consulates General in Shanghai and Bombay and also to resume border trade.

The Chinese Government has expressed its satisfaction with the improvement of India-China relations, and has expressed confidence that these relations will further improve and develop.